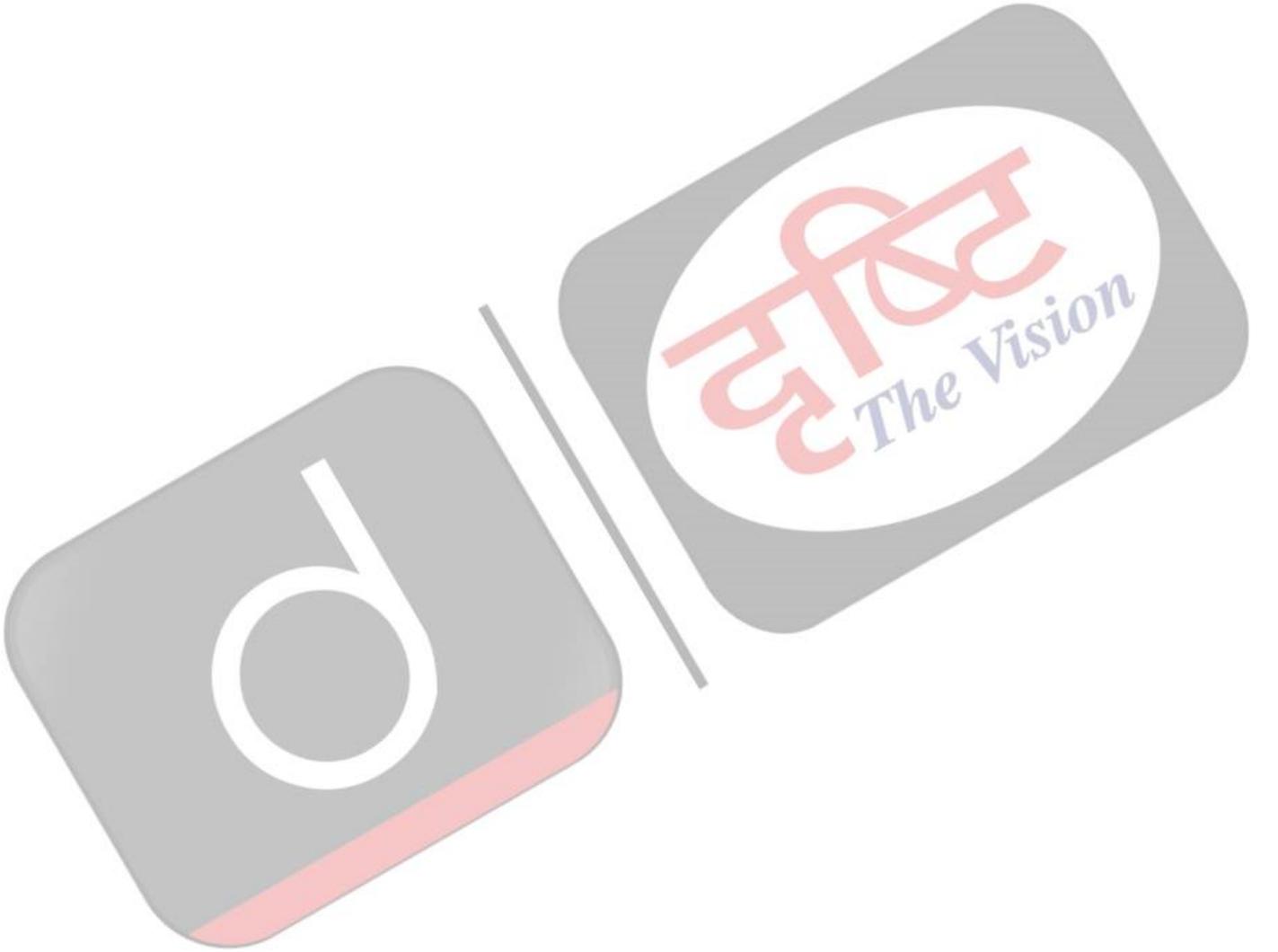




मौद्रिक नीतिसमिति



# मौद्रिक नीति समिति

## Monetary Policy Committee

### मौद्रिक नीति समिति

#### ★ प्राधिकरण:

- ★ भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत मौद्रिक नीति के निर्माण हेतु अधिकृत है।

#### ★ उद्देश्य:

- ★ मूल्य स्थिरता और स्थिर विदेशी मुद्रा मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिये मुद्रास्फीति या ब्याज दरों को समायोजित करना।

### मौद्रिक नीति समिति (MPC)

#### ★ कानूनी ढाँचा:

- ★ संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत।
  - ❖ केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
- ★ MPC को वर्ष में कम-से-कम चार बार बैठक करनी होती है। MPC के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, और वोटों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है।

### संघटन

- ★ आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में।
- ★ मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर।
- ★ केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी।
- ★ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तीन व्यक्ति।

### कार्य

- ★ मौद्रिक नीति समिति रेपो दर निर्धारित करती है।
  - ❖ यह वह दर है, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियाँ खरीदकर उधार देता है।
  - ❖ यह अर्थव्यवस्था में अन्य सभी ब्याज दरों के लिये एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है।
- ★ हर छह महीने में एक बार RBI को मुद्रास्फीति के स्रोतों और 6-18 महीनों की अवधि के लिये मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान की व्याख्या करने हेतु 'मौद्रिक नीति रिपोर्ट' नामक एक दस्तावेज प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।

[और पढ़ें...](#)

भारत कोवडि -19 खरीद: चुनौतियाँ, नवाचार और सबक

प्रलिमिंस के लिये:

## मेन्स के लयि:

महतत्वपूरण अंतरराष्टरीय संस्थान, कोवडि -19 का प्रबंधन ।

## चरचा में क्यो?

हाल ही में वशिव बैंक ने "भारत कोवडि -19 खरीद: चुनौतियाँ, नवाचार और सबक (India Covid-19 Procurement: Challenges, Innovations, and Lessons )" शीर्षक से एक रपौरट जारी की है, जसके अनुसार, भारत महामारी के प्रबंधन में वभिन्न चीजें हासलि करने में कामयाब रहा ।

- यह रपौरट कोवडि महामारी के गंभीर प्रारंभिक चरण के दौरान आवश्यक चकितिसा वस्तुओं की नरितर आपूर्त सिुनश्चिति करने के लयि भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर करीब से नज़र डालती है ।

## प्रमुख बदि

- वैश्वकि:
  - वैश्वकि स्वास्थय सुरक्षा सूचकांक में उच्च रेटगि वाले देशों सहति अधकिंशदेशों की स्वास्थय प्रणालयिों को महामारी से नपिटने में नई चुनौतयिों का सामना करना पडा ।
  - असाधारण बाज़ार अनश्चितताओं को दूर करने के लयि कई देशों ने आपातकालीन संदर्भ में प्रक्रयिओं को उत्तरदायी बनाने के लयि सार्वजनकि खरीद में नवाचारों की शुरुआत की ।
- भारतीय पहल:
  - भारत ने देश भर में चकितिसा आपूर्त के कुशल वतरण का प्रबंधन कयिा, शुरुआती प्रतबंधि लगाए और आपात स्थति के दौरान त्वरति खरीद नरिणय हेतु सशक्त अंतर-मंत्रालयी समूह भी बनाए ।
  - भारत चार महीने की अवधि के भीतर तेज़ी से जो पहले केवल 18 थी से सीधे 2,500 से अधकि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने में कामयाब रहा और वैश्वकि आपूर्त शृंखलाओं के लयि गंभीर चुनौतयिों का सामना करने वाली भवषिय की महामारयिों एवं स्वास्थय आपात स्थतयिों का सामना करने हेतु तैयार हो गया ।
  - भारत ने स्वदेशी चकितिसा उपकरण उद्योग के वकिस के लयि अनुकूल वातावरण भी तैयार कयिा ।
  - कोवडि -19 महामारी से पहले भारत ज़्यादातर वेंटलिटर का आयात कर रहा था, हालाँकि कई नए लोगों सहति 25 नरिमाता 'सीमति वत्तीय और बुनयिादी ढाँचा कषमता वाले वेंटलिटर' का उत्पादन करने के लयि आगे आए ।
  - सरकार ने वेंटलिटर बनाने के लयि कई ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल नरिमाण कंपनयिों का उपयोग कयिा ।
- भारत में प्रमुख नवाचार:
  - स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहति करने के लयि पूरे सरकारी दृष्टकिण को अपनाने से इकाई कीमतों और वैश्वकि आपूर्त पर नरिभरता को कम करने में मदद मलिी ।
  - त्वरति नविदि प्रक्रयिा और गुणवत्ता आश्वासन प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई ।
  - कुशल आपूर्त शृंखला प्रबंधन को कम्प्यूटरीकृत मॉडलगि द्वारा संचालति कयिा गया जसिने महामारी वजिज्ञान के रुझानों के आधार पर राजयों के बीच ऑक्सीजन और गहन देखभाल इकाई आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की ।
  - सरकार की ई-खरीद साइट पर गुणवत्ता आश्वासति कोवडि वस्तुओं को तेज़ी से स्थानांतरति करना, जसिने राजयों को नविदि प्रक्रयिा से गुजरे बनिा प्रतसिपर्दधी कीमतों पर इन उत्पादों तक पहुँच शुरु करने में सक्षम बनाया ।

## वशिव बैंक:

- परिचय:
  - अंतरराष्टरीय पुनरनरिमाण और वकिस बैंक (IBRD) तथा अंतरराष्टरीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में बरेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी । अंतरराष्टरीय पुनरनरिमाण और वकिस बैंक (IBRD) को ही वशिव बैंक के रूप में जाना जाता है ।
  - वशिव बैंक समूह वकिसशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धिका नरिमाण करने वाले स्थायी समाधानों के लयि काम कर रहे पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्वकि साझेदारी है ।
- सदस्य:
  - 189 देश इसके सदस्य हैं ।
  - भारत भी एक सदस्य देश है ।
- प्रमुख रपौरट:
  - [ईज़ ऑफ़ डुइंग बिज़नेस](#) (हाल ही में इसका प्रकाशन बंद कर दयिा गया)
  - [हयुमन कैपटिल इंडेक्स](#)
  - [वर्ल्ड डेवलपमेंट रपौरट](#)
- पाँच वकिस संस्थान

- अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD)
- अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
- अंतरराष्ट्रीय वित्त नगिम (IFC)
- बहुपक्षीय नविश गारंटी एजेंसी (MIGA)
- नविश विवादों के नपिटारे के लयि अंतरराष्ट्रीय केंद्र (ICSID)
  - भारत इसका सदस्य नहीं है ।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न 'वशिव आर्थकि संभावना (ग्लोबल इकनॉमकि प्रॉस्पेक्टर्स)' रपिर्ट आवधकि रूप से नमिनलखिति में से कौन जारी करता है?

- एशया विकास बैंक
- यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (यूरोपयिन बैंक फॉर रकिंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट)
- यू.एस.फेडरल रज़िर्व बैंक
- वशिव बैंक

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- वशिव आर्थकि संभावना (ग्लोबल इकनॉमकि प्रॉस्पेक्टर्स)' रपिर्ट वशिव अर्थव्यवस्था की स्थिति पर वशिव बैंक का प्रमुख अरद्धवार्षकि प्रकाशन है ।
- वशिव बैंक द्वारा प्रकाशति अन्य महत्त्वपूर्ण रपिर्ट 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' और 'वर्ल्ड डेवलपमेंट रपिर्ट' हैं ।

अतः विकल्प (d) सही है ।

प्रश्न. सार्वभौम अवसंरचना सुवधि (ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ैसलिटी) है: (2017)

- एशया में अवसंरचना उन्नयन के लयि ASEAN का उपकरण है, जो एशयाई विकास बैंक द्वारा दयि गए साख (क्रेडिट) से वतितपोषति है ।
- गैर-सरकारी कषेत्तरक और संस्थागत नविशकों की पूंजी का संग्रहण करने के लयि वशिव बैंक का सहयोग है, जो जटलि अवसंरचना सार्वजानकि-नजिी भागीदारयिों (PPPs) की तैयारी और संरचना-नरिमाण को आसान बनाना है ।
- यह OECD के साथ कार्य करने वाले वशिव के प्रमुख बैंकों का सहयोग है, जो उन अवसंरचना परयोजनाओं को वसितारति करने पर केंद्रति है, जनिमें गैर-सरकारी वनिविश संग्रहीत करने की क्षमता है ।
- UNCTAD द्वारा वतितपोषति उपकरण है जो वशिव में अवसंरचना विकास को वतितपोषति करने और आसान बनाने का प्रयास करता है ।

उत्तर: (b)

प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में दखिने वाले 'आइएफसी-मसाला बॉन्ड (IFC Masals Bonds)' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. अंतरराष्ट्रीय वतित नगिम (इंरनैशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन), जो इन बॉन्डों को प्रस्तावति करता है, वशिव बैंक की एक शाखा है ।
2. ये रूपया अंकति मूल्य वाले बॉन्ड (Rupee-denominated Bonds) हैं और सार्वजनकि एवं नजिी कषेत्तरक के ऋण वतितयिन के स्रोत हैं ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि ।

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. वशिव बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त रूप से बरेटन वुड्स नाम से जानी जाने वाली संस्थाएँ, वशिव की आर्थकि व वतितयिीय व्यवस्था की संरचना का संभरण करने वाले दो अंतरसरकारी स्तम्भ हैं । पृष्ठीय रूप में वशिव बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की अनेक समान वशिष्टिताएँ हैं, तथापि उनकी भूमकि, कार्य तथा अधदिश स्पष्ट रूप से भनिन हैं । व्याख्या कीजयि । (मेन्स-2013)

[स्रोत: द हद्रि](#)

## क्लाउड सीडिंग

### प्रलिस के लिये:

क्लाउड सीडिंग और उसके प्रकार, कृत्रिम वर्षा, वर्षण, संघनन।

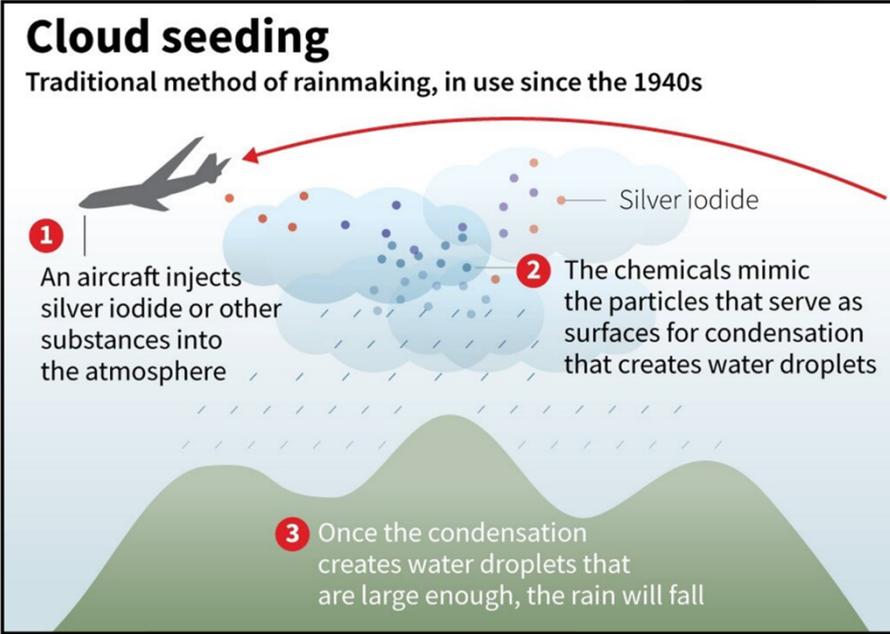
### मेन्स के लिये:

क्लाउड सीडिंग का अनुप्रयोग और चर्चा।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जो पृथ्वी पर सबसे गर्म और सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक में स्थित है, क्लाउड सीडिंग और वर्षण को बढ़ाने के प्रयास का नेतृत्व कर रहा है, जहाँ प्रतिवर्ष औसतन 100 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है।

- संयुक्त अरब अमीरात ने एक नई तकनीक के अंतर्गत संघनन प्रक्रिया को प्रोत्साहित और तेज़ करने के लिये बादलों में नमक के नैनोकणों तथा जल को आकर्षित करने वाले 'साल्ट फ्लेयर्स' को संयुक्त किया है। उम्मीद है कि यह तकनीक वर्षा के रूप में गरिने के लिये पर्याप्त बूँदों का उत्पादन करेगी।



## क्लाउड सीडिंग:

- परचिय:**
  - क्लाउड सीडिंग, सूखी बर्फ या सामान्यतः सलिवर आयोडाइड एरोसोल के बादलों के ऊपरी हिस्से में छड़िकाव की प्रक्रिया है ताकि वर्षण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करके वर्षा कराई जा सके।
  - क्लाउड सीडिंग में छोटे कणों को विमानों का उपयोग कर बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। छोटे-छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं और संघनन से उसका दरव्यमान बढ़ जाता है। इससे जल की भारी बूँदें बनकर वर्षा करती हैं।
  - क्लाउड सीडिंग से वर्षा दर प्रतिवर्ष लगभग 10% से 30% तक बढ़ जाती है और क्लाउड सीडिंग के संचालन में वलिवणीकरण प्रक्रिया की तुलना में बहुत कम लागत आती है।
- क्लाउड सीडिंग के तरीके:**
  - हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग:**
    - बादलों के नचिले हिस्से में ज्वालाओं या वसिफोटकों के माध्यम से नमक को फैलाया जाता है, और जैसे ही यह पानी के संपर्क में आता है नमक कणों का आकार बढ़ने लगता है।
  - स्टेटिक क्लाउड सीडिंग:**

- इसमें सल्फर आयोडाइड जैसे रसायन को बादलों में फैलाया जाता है। सल्फर आयोडाइड एक क्रिस्टल का उत्पादन करता है जिसके चारों ओर नमी संघनित हो जाती है।
- वातावरण में उपस्थिति जलवाष्प को संघनित करने में सल्फर आयोडाइड अधिक प्रभावी है।
- **डायनेमिक क्लाउड सीडिंग:**
  - इसका उद्देश्य ऊर्ध्ववाधर वायु राशियों को बढ़ावा देना है जो बादलों से गुजरने हेतु अधिक जल को प्रोत्साहित करता है, जिससे वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है।
  - प्रक्रिया को स्थिति, क्लाउड सीडिंग, की तुलना में अधिक जटिल माना जाता है क्योंकि यह अनुकूल घटनाओं के अनुक्रम पर निर्भर करता है।
- **क्लाउड सीडिंग के अनुप्रयोग:**
  - **कृषि:**
    - इसके द्वारा **सुखाग्रस्त क्षेत्रों** में कृत्रिम वर्षा के माध्यम से राहत प्रदान की जाती है।
      - उदाहरण के लिये, वर्ष 2017 में कर्नाटक में 'वर्षाधारी परियोजना' के अंतर्गत कृत्रिम वर्षा कराई गई थी।
  - **वदियुत उत्पादन:**
    - क्लाउड सीडिंग के अनुप्रयोग द्वारा **तस्मानिया (ऑस्ट्रेलिया)** में पछिले 40 वर्षों के दौरान **जल वदियुत उत्पादन** में वृद्धि देखी गई है।
  - **जल प्रदूषण नियंत्रण:**
    - क्लाउड सीडिंग गर्मियों के दौरान **नदियों के न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखने** में मदद कर सकती है और **नगर पालिकाओं तथा उद्योगों से उपचारित अपशिष्ट जल के नखन के प्रभाव को भी कम** कर सकती है।
  - **कोहरा का प्रसार, ओला वर्षण और चक्रवात की स्थिति में परिवर्तन:**
    - सर्दियों के दौरान **क्लाउड सीडिंग का उपयोग पर्वतों पर बर्फ की परत का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है**, ताकविसंत के मौसम में बर्फ के पिघलने के दौरान **अतिरिक्त अपवाह प्राप्त** हो सके।
    - कोहरा के प्रसार, ओला वर्षण और चक्रवात की स्थिति में परिवर्तन के उद्देश्य से क्लाउड सीडिंग के माध्यम **समौसम में परिवर्तन के लिये वर्ष 1962 में अमेरिका में "प्रोजेक्ट स्काई वाटर"** का परिचालन किया गया था।
  - **वायु प्रदूषण में कमी:**
    - वर्षा के माध्यम से जहरीले **वायु प्रदूषकों** को कम करने के लिये 'क्लाउड सीडिंग' का संभावित रूप से उपयोग किया जा सकता है।
    - **उदाहरण:** हाल ही में **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** ने अन्य शोधकर्ताओं के साथ **दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिये क्लाउड सीडिंग के उपयोग पर** विचार किया।
  - **पर्यटन:**
    - क्लाउड सीडिंग द्वारा **शुष्क क्षेत्रों को अनुकूलित कर पर्यटन को बढ़ावा** दिया जा सकता है।

## क्लाउड सीडिंग में वदियमान चुनौतियाँ:

- **संभावित दुष्प्रभाव:**
  - क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले रसायन **पौधों, जानवरों और लोगों या पर्यावरण** के लिये संभावित रूप से हानिकारक हो सकते हैं।
- **असामान्य मौसम प्रतरूप:**
  - यह अंततः गृह पर **जलवायु प्रतरूप में बदलाव** ला सकता है। वर्षा को प्रोत्साहित करने के लिये वातावरण **में रसायनों को छड़कने की कृत्रिम प्रक्रिया** के कारण सामान्य रूप से वर्षा वाले प्राप्त स्थानों पर सूखे जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है।
- **तकनीकी रूप से महंगा:**
  - इसमें रसायनों को **आकाश में छड़कने और उन्हें फ्लेयर शॉट्स या हवाई जहाज़** द्वारा हवा में छोड़ने जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जिसमें भारी लागत और लॉजिस्टिक शामिल है।
- **प्रदूषण:**
  - कृत्रिम वर्षा के दौरान **सल्फर आयोडाइड, शुष्क बर्फ या लवण जैसे सीडिंग तत्व** भी धरातल पर आएंगे। क्लाउड-सीडिंग परियोजनाओं के आस-पास के स्थानों में खोजे गए अवशिष्ट चाँदी को वषिकृत माना जाता है। शुष्क बर्फ के लिये **यहारीनहाउस गैस का एक स्रोत** भी हो सकता है जो **ग्लोबल वार्मिंग** में योगदान देता है, क्योंकि यह मूल रूप से **कार्बन डाइऑक्साइड** होता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न: नमिनलखिति में से कसिके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ वरिलन तकनीक तथा समतापमंडल में सल्पेट वायुवलिय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? (2019)

- कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिये
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिये
- पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये
- भूमंडलीय तापन को कम करने के लिये

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- पक्ष्वाभ मेघ वरिलन तकनीक एक प्रकार की तकनीक है जिसमें उच्च ऊँचाई के पक्ष्वाभ बादलों को पतला करना शामिल है। पक्ष्वाभ बादल अंतरिक्ष में सौर विकिरण को पूरगत: प्रतबिबिति नहीं करते हैं, लेकिन ये उच्च ऊँचाई और नमिन तापमान पर बनते हैं, इसलिये ये बादल दीर्घ विकिरण को अवशोषति करते हैं और ग्रीनहाउस गैसों के समान जलवायु प्रभाव डालते हैं। पतले पक्ष्वाभ बादलों के नाभकि (जैसे धूल) को उन क्षेत्रों में अंतःक्षेपण करके प्राप्त कथिा जाएगा जहाँ पक्ष्वाभ बादल है
- ये बर्फ के क्रस्टल को बड़ा बनाते हैं और पक्ष्वाभ बादल को पतला करते हैं। बादलों को पतला करने से अधिक गर्मी अंतरिक्ष में चली जाएगी और इस तरह पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो जाएगा।
- समतापमंडल वायुवलय अंतःक्षेपण (Stratospheric Aerosol Injection-SAI) ऐसी तकनीक है, जिसमें बड़ी मात्रा में अकार्बनकि कणों (जैसे, सलफर डाइऑक्साइड) का समतापमंडल में छड़िकाव करना शामिल है, जो आने वाले विकिरण के लयि परावर्तक बाधा के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है।

अतः विकल्प (d) सही है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## मुस्लमि परसनल लॉ केस

### प्रलिमिस के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

### मेन्स के लयि:

भारत में परसनल लॉ और संबंधति मुद्दे, महिलाओं से संबंधति मुद्दे

## चर्चा में क्यों?

मुस्लमि परसनल लॉ द्वारा अनुमत बहु वविाह और नकिाह हलाला की प्रथा की संवैधानकि वैधता को चुनौती देने वाली कई याचकिाओं को [सर्वोच्च न्यायालय](#) में सूचीबद्ध कथिा गया है।

- पाँच न्यायाधीशों की संवधान पीठ ने [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(National Human Rights Commission-NHRC\)](#), [राष्ट्रीय महिला आयोग \(National Commission of Women-NCW\)](#) और [राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग](#) को नोटसि जारी की है।

## याचकिाकर्त्ताओं के तरक:

- याचकिाकर्त्ताओं ने **बहुवविाह और नकिाह-हलाला** पर प्रतबिंध लगाने की मांग करते हुए कहा है कथिह मुस्लमि महिलाओं को असुरक्षति और कमज़ोर बनाता है एवं उनके **मौलकि अधिकारों का उल्लंघन** करता है।
- उन्होंने मांग की कथि **मुस्लमि परसनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधनियम की धारा 2** को असंवैधानकि घोषति कथिा जाए और संवधान के **अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार)**, **15 (धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतबिध)** और **21 (जीवन का अधिकार)** के उल्लंघनकर्त्ता के रूप में घोषति कथिा जाए जो बहुवविाह और नकिाह-हलाला की प्रथा को मान्यता प्रदान करता है।
- संवधान **व्यक्तगित कानूनों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता** है, इसलिये सर्वोच्च न्यायालय इन प्रथाओं की संवैधानकि वैधता के मुद्दे की जाँच नहीं कर सकता है।
- याचकिाकर्त्ताओं का तरक है कथिहाँ तक कथि शीर्ष न्यायालय और वभिनिन उच्च न्यायालयों ने भी अन्य अवसरों पर परसनल लॉ द्वारा स्वीकृत प्रथाओं के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दथिा है, याचकिाकर्त्ताओं द्वारा **तीन तालक** चुनौती मामले को सर्वोच्च न्यायालय पहले ही खारज़ि कर चुका है।

## मुस्लमि परसनल लॉ:

- शरथिा या मुस्लमि परसनल लॉ के अनुसार, **पुरुषों को बहुवविाह करने की अनुमति दी गई** है, जसिका अर्थ है वे एक ही समय में एक से अधिक पत्नयिों के साथ रह सकते हैं, वविाह की **अधिकतम संख्या 4** नरिधारति की गई है।
- **'नकिाह हलाला'** एक ऐसी प्रकरथिा है जसिमें एक मुस्लमि महिला को अपने तलाकशुदा पतसिसे दोबारा शादी करने से पूर्व दूसरे व्यक्तसिसे शादी करनी होती है और फरि उससे तलाक लेना पड़ता है।

## भारत में मुस्लिम कानून:

- मुस्लिम प्रसनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम (Shariat Application Act) वर्ष 1937 में भारतीय मुसलमानों के लिये इस्लामी कानून सहिता तैयार करने के उद्देश्य से पारित किया गया था।
- ब्रिटिश जो उस समय भारत पर शासन कर रहे थे, यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीयों पर उनके अपने सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार शासन किया जाए।
- जब हद्दियों और मुसलमानों के लिये बनाए गए कानूनों के बीच अंतर करने की बात आई, तो उन्होंने यह बयान दिया कि हद्दियों के मामले में **उपयोग का स्पष्ट प्रमाण कानून की लिखित सहिता से अधिक होगा**। दूसरी ओर मुसलमानों के लिये कुरान में लिखित सहिता सबसे महत्वपूर्ण होगी।
- वर्ष 1937 के बाद से शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम मुस्लिम सामाजिक जीवन के पहलुओं, जैसे शादी, तलाक, वरिस्त और पारिवारिक संबंधों को अनिवार्य करता है। अधिनियम के अनुसार, व्यक्तिगत विवाद के मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा।

## अन्य धर्मों के प्रसनल लॉ:

- **हद्द उत्तराधिकार अधिनियम, 1956** जो हद्दियों, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच संपत्ति वरिस्त के दशा-नरिदेश देता है।
- पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 पारसियों द्वारा उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार पालन किये जाने वाले नियमों को नरिधारित करता है।
- **हद्द विवाह अधिनियम, 1955** ने हद्दियों के बीच विवाह से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध किया था।

## भारत में शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम अपरविर्तनीय:

- शरीयत अधिनियम की प्रयोज्यता वर्षों से विवादास्पद रही है। ऐसे उदाहरण पहले भी देखे गए हैं जब व्यापक मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण का मुद्दा धार्मिक अधिकारों के साथ विवाद में आ गया।
- इनमें सबसे चर्चित **शाह बानो मामला** है।
  - वर्ष 1985 में 62 वर्षीय शाह बानो ने अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उसके गुजारा भत्ता के अधिकार को बरकरार रखा लेकिन इस फैसले का इस्लामिक समुदाय ने कड़ा वरिध किया था, जो इसे कुरान में लिखित नियमों के खिलाफ मानते थे। इस मामले ने इस बात को लेकर विवाद पैदा कर दिया कि न्यायालय किस हद तक व्यक्तिगत/धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
- भारत में शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम प्रसनल लॉ संबंधों में इस्लामी कानूनों के अनुप्रयोग की रक्षा करता है, लेकिन यह अधिनियम कानूनों को परभाषित नहीं करता है।
- प्रसनल लॉ संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत 'कानून' की परभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। प्रसनल लॉ की वैधता को संविधान में नहि **मौलिक अधिकारों** के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की रक्षा करता है? (2019)

- (a) अनुच्छेद 19
- (b) अनुच्छेद 21
- (c) अनुच्छेद 25
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- शादी का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक घटक है, जिसमें कहा गया है कि "किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा"।
- लता सहि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शादी के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक घटक के रूप में देखा।

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

प्रश्न. रीतिरिवाज और परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगतविरिध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? (मेन्स-2020)

**स्रोत: द हद्द**

## एंटी रेडिएशन पलिस

### प्रलिमिस के लिये:

पोटेशियम आयोडाइड, थायराइड ग्रंथि, डब्ल्यूएचओ।

### मेन्स के लिये:

एंटी-रेडिएशन पलिस।

## चर्चा में क्यों?

यूक्रेन के ज़पोरिज़िया बजिली संयंत्र में एक परमाणु आपदा की आशंका के कारण यूरोपीय संघ ने उसके आसपास के नवासियों के बीच वितरित करने के लिये 5.5 मिलियन एंटी-रेडिएशन गोलीयों की आपूर्ति करने का फैसला किया है।

## रेडिएशन इमरजेंसी:

- ये अनयोजित या आकस्मिक घटनाएँ हैं जो मनुष्यों और पर्यावरण के लिये रेडियो-परमाणु खतरा पैदा करती हैं।
- ऐसी स्थितियों में रेडियोधर्मी स्रोत से विकिरण जोखिम शामिल होता है और खतरे को कम करने के लिये तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
- ऐसी आपात स्थिति से निपटने में विकिरण रोधी गोलीयों का उपयोग भी किया जाता है।

## एंटी रेडिएशन पलिस:

- पोटेशियम आयोडाइड (KI) की गोलीयों या विकिरण रोधी गोलीयों, विकिरण जोखिम के मामलों में कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिये जानी जाती हैं।
- इनमें गैर-रेडियोधर्मी आयोडीन होता है और यह थायरॉयड ग्रंथि में रेडियोधर्मी आयोडीन को और बाद में सांद्रता को अवरोध करने में मदद कर सकता है।

## पलिस का कार्य:

- विकिरण रसाव के बाद, रेडियोधर्मी आयोडीन वायु में फैल जाता है तथा भोजन, जल और मूदा को दूषित करता है।
- आंतरिक जोखिम या विकिरण तब होता है जब रेडियोधर्मी आयोडीन शरीर में प्रवेश करता है और थायरॉयड ग्रंथि में जमा हो जाता है।
  - थायरॉयड ग्रंथि, शरीर के चयापचय को नियंत्रित करने के क्रम में हार्मोन का उत्पादन करने के लिये आयोडीन का उपयोग करती है, यह ग्रंथि गैर-रेडियोधर्मी और रेडियोधर्मी आयोडीन के मध्य विभेद करने में सक्षम नहीं होती है।
- पोटेशियम आयोडाइड (KI) की टैबलेट 'थायरॉयड ब्लॉकगि' के लिये इसी पर निर्भर करती हैं।
- विकिरण के संपर्क में आने से कुछ घंटे पहले या उसके तुरंत बाद ली गई पोटेशियम आयोडाइड (KI) की टैबलेट यह सुनिश्चित करती हैं कि गैर-रेडियोधर्मी आयोडीन थायराइड ग्रंथि में पूरी तरह से अपना स्थान घेर ले।
- इससे थायराइड ग्रंथि पूर्णतः भर जाती है और अगले 24 घंटों के लिये किसी भी स्थिति या रेडियोधर्मी आयोडीन को अवशोषित नहीं कर सकती है।
- लेकिन पोटेशियम आयोडाइड गोलीयों केवल नविकरक औषधि हैं जो विकिरण द्वारा थायरॉयड ग्रंथि को हुई किसी भी क्षतिकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती हैं।
- एक बार जब थायरॉयड ग्रंथि रेडियोधर्मी आयोडीन को अवशोषित कर लेती है तो उस व्यक्ति में थायराइड कैंसर होने का खतरा अधिक होता है।

## वधि पूर्णतः सुरक्षित:

- एंटी-रेडिएशन पलिस 100% सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं।
- पोटेशियम आयोडाइड की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर में कतिना रेडियोधर्मी आयोडीन है और यह कतिनी जल्दी शरीर में अवशोषित हो जाता है।
- साथ ही पलिस हर उम्र के लोगों के लिये उपलब्ध नहीं हैं। इसे केवल 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिये अनुशंसित किया गया है।

## [स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

### प्रलिम्स के लिये:

मारजिआना/गांजा, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, भाँग, 'नशा मुक्त भारत' या ड्रग-मुक्त भारत अभियान

### मेन्स के लिये:

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि [स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम \(NDPS\) अधिनियम, 1985](#) के अनुसार भाँग को कहीं भी प्रतर्बिधति पेय या नषिदिध ड्रग्स के रूप में संदरभति नहीं कयिा गया है ।

- उच्च न्यायालय ने पूरव के दो नरिण्यों मधुकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2002 और अरजुन सहि बनाम हरयिाणा राज्य, 2004 का आधार लेते हुए कहा कि पूरव नरिण्यों में भी कहा गया है कि भाँग को गांजा/मारजिआना की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, अतः NDPS अधिनियम के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं ।
- कुछ माह पूरव ही [थाईलैंड ने मारजिआना/गांजे की खेती को वैध](#) कर दयिा है, हालाँकि इसके मनोरंजक उपयोग (जैसे धूम्रपान) पर अभी भी प्रतर्बिधति है ।

## भाँग:

- परचियः
  - इसका वैजज्ञानकि नाम **कैनबसि इंडिका (Cannabis Indica)** है । यह एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी पत्तियों को पीस कर भाँग तैयार की जाती है, जिसे अक्सर वभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ ठंडाई और लस्सी जैसे पेय में मलियाा जाता है ।
  - भाँग का सेवन भारतीय उपमहाद्वीप में सदयियों से कयिा जाता रहा है और होली एवं महाशविरात्र जैसे त्योहारों के अवसर पर इसका व्यापक रूप से सेवन कयिा जाता है ।
- कानूनः
  - NDPS अधिनियम, 1985 में अधिनियमति मुख्य कानून है, जो ड्रग्स और उसकी तस्करी से संबंधति है ।

## स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानः

- यह भाँग को एक मादक औषधि के रूप में परभाषति करता हैः
  - एनडीपीएस अधिनियम भाँग (हेम्प) को पौधे को उन हसिसों के आधार पर एक मादक दवा के रूप में परभाषति करता है जो इसके दायरे में आते हैं । अधिनियम इन भागों को इस प्रकार सूचीबद्ध करता हैः
    - **चरसः** चरस कैनबसि के पौधे से निकले रेजनि से तैयार होता है । यह रेजनि भी इस पौधे का हसिसा है, रेजनि पेड़-पौधों से निकलने वाला चपिचपि पदार्थ है । इसे ही चरस, हशीश और हैश कहा जाता है । भारत में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत कैनबसि के कसिी भी तरह के सेवन पर प्रतर्बिधति है ।
    - **गांजाः** भाँग और गांजा एक ही प्रजाति के पौधे से बनाए जाते हैं । भाँग के पौधे के फूल या फूलने वाले शीर्ष का उपयोग गांजा के रूप में कयिा जाता है ।
    - भाँग के उपरोक्त रूपों में से कसिी के भी या उससे तैयार कसिी भी पेय या उससे नरिमति मशिरण ।
  - अधिनियम अपनी परभाषा में शीर्ष पर न होने के कारण बीज और पत्तियों को शामिल नहीं करता है ।
  - NDPS अधिनियम में भाँग का जकिर नहीं है ।
- सजाः
  - NDPS अधिनियम की धारा 20 अधिनियम में परभाषति भाँग के उत्पादन, नरिमाण, बकिरी, खरीद, आयात और अंतर-राज्यीय नरियात के लयि दंड का प्रावधान करती है । नरिधारति सजा ज़ब्त की गई दवाओं की मात्रा पर आधारति है ।
  - यह कुछ मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान करता है जहाँ एक व्यक्ती बार-बार अपराधी हो ।

## NDPS अधिनियम के तहत अपराध की स्थतिः

- राष्ट्रीय अपराध रकिर्कड ब्यूरो (NCRB) के वर्ष 2021 के हालयिा आँकड़ों के अनुसार, पंजाब अपराध दर की सूची में सबसे शीर्ष पर है ।
  - पंजाब में वर्ष 2021 में 32.8% अपराध दर दर्ज की गई, जो देश में सबसे ज़यादा थी ।
- हमिाचल प्रदेश 20.8% की अपराध दर के साथ दूसरे स्थान पर रहा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ने NDPS अधिनियम की अपराध दर 17.2% दर्ज

की, उसके बाद केरल (16%) का स्थान रहा।

- वर्ष 2021 में NDPS अधिनियम के तहत सबसे कम अपराध दर केंद्रशासित प्रदेश दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव (0.5%) में दर्ज की गई, इसके बाद गुजरात (0.7%) और बिहार (1.2%) राज्यों का स्थान है।

## नशीली दवाओं की लत से नपिटने के लिये पहल:

- नार्को-समनवय केंद्र:** **नार्को-समनवय केंद्र (NCORD)** का गठन नवंबर 2016 में किया गया था और "नारकोटिक्स नयितरण के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता" योजना को पुनर्जीवित किया गया था।
- ज़बती सूचना प्रबंधन प्रणाली:** नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक नया सॉफ्टवेयर यानी ज़बती सूचना प्रबंधन प्रणाली (SIMS) विकसित करने के लिये धन उपलब्ध कराया गया है जो नशीली दवाओं से संबंधित अपराध और अपराधियों का एक पूरा ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करेगा।
- नेशनल ड्रग एब्यूज़ सर्वे:** सरकार एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की मदद से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के रुझानों को मापने हेतु राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग संबंधी सर्वेक्षण भी कर रही है।
  - प्रोजेक्ट सनराइज़:** इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में भारत में उत्तर-पूर्वी राज्यों में **बढ़ते एचआईवी प्रसार** से नपिटने के लिये शुरू किया गया था (खासकर ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने वाले लोगों के बीच)।
- 'नशा मुक्त भारत'** या ड्रग मुक्त भारत अभियान

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक राज्यों से भारत की नकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है. नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिये। इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या-क्या प्रतरोधी उपाय किये जाने चाहिये? (मेन्स-2018)

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/01-09-2022/print>

